THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) to (c). Under the Northern Rice Zone (Movement Control) Order, 1968 issued by the Government of India, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Chandigarh and Delhi together constitute a composite rice zone called the Northern Rice Zone. By implication, the movement of rice inside the Northern Rice Zone is free from restrictions and ordinarily no permit is required for bringing rice from Pathankot (Punjab) to Delhi.

In order to check evasion of levy and to prevent the smuggling of rice, the Government of Punjab are regulating the movement of levy-free rice under movement chits issued by the district officers.

**Bird Sancturies in Madhya Pradesh during Fifth Plan**

2624. SHRI BHAGIRATH BHANWAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government propose to set up two bird sancturies at Noorabad in Gwalior district, and Sirpur in Raipur district during the Fifth Plan period under the project 'Save Tiger Programme' sponsored by the Central Government;

(b) if so, the total expenditure incurred thereon; and

(c) when the work will have been completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINSITRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL): (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as the information is received.

**संविधान के अनुच्छेद 48 के बारे में पुनर्गठित गो रक्षा समिति की सिफारिशें**

2625. **श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 सितम्बर, 1973 को पुनर्गठित गो-रक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सारे देश में अविलम्ब संविधान के अनुच्छेद 48 को लागू करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) अगर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल ):** (क) से (ग): गो-रक्षा समिति की 17 सितम्बर, 1973 को हुई बैठक में क प्रस्ताव पारित किया गया था । चूंकि संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 2 की प्रविष्टि 15 में गायों के परिरक्षण रक्षा और सुधार का विषय राज्यों का विषय है, अत: उच्चतम न्यायालय की व्याख्यानुसार संविधान के 48 वें अनुच्छेद के क्रियान्वयन की और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान पुन: दिलाया गया था । गो वंश की रक्षा संबंधी सारे प्रश्न पर गो-रक्षा समिति विचार कर रही है । इसकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है । समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने और इसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय किये जाने के बाद ही इस बारे में सरकार के लिये अगली कार्रवाई करना संभव हो सकेगा ।

**Long Term Dry Irrigation Plan**

2626. SHRI MARTAND SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether in view of repeated failure of monsoon in this country, Government propose long term dry irrigation plans and exploitation of underground water potential in the country so that food balance may not